श्री कमल नाथ : सर, NHAI इसे contract पर देते हैं और जिसको contract मिलता है, उसको इसकी पूर्ति करनी पड़ती है। अगर कोई ऐसी विशेष बात है, जिस पर माननीय सदस्य मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो वे मुझे सूचित करें, मैं इसको check करूंगा, पर जो राज्य के श्रम विभाग हैं, वे इस पर आवश्यक checking करते रहते हैं।

श्री मोहम्मद अमीन : आप राज्य सरकारों की मीटिंग बुलाइए और इन बातों के ऊपर फैसला कीजिए, नहीं तो यह कभी हो नहीं पाएगा।

جناب محمد امین صاحب : آپ راجئے سرکاروں کی میٹنگ بلائیے اور ان باتوں کے اوپر فیصلہ کیجئے، نہیں تو یہ کبھی ہو نہیں پائے گا۔

श्री शिवानन्द तिवारी : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार में नैशनल हाइवे की कितनी किलोमीटर सड़के हैं और 2004 से अब तक इन सड़कों की मरम्मत के लिए और इनको मजबूत बनाने के लिए, इनके सुदृढ़ीकरण के लिए अब तक कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

SHRI KAMAL NATH: Sir, this is regarding Bihar. I will be happy to send this information to the hon. Member.

देश में अवैध हथियारों का धड़ल्ले से निर्माण किया जाना

*265. **श्री भगत सिंह कोश्यारी** :[]

श्री प्रभात झा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि देश के कई भागों में अवैध हथियार बनाने के कारखाने खुलेआम चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास यह सूचना है कि ये कारखाने पुलिस की मिलीभगत से चल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो अभी तक कोई गंभीर कदम न उठाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार इन कारखानों एवं सम्बद्ध पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (ङ) कुछ उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि कुछ राज्यों में अवैध हथियारों और गोलाबारूद विनिर्माण की ऐसी यूनिटें मौजूद हैं जहां गुप्त रूप से कुटीर स्तर पर घरेलू यूनिटों के माध्यम से इनका विनिर्माण किया जाता है।

इस संबंध में और ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र किया जाना है। अपेक्षित सूचना एकत्र करने के लिए कार्रवाई चल रही है और इसे उचित समय पर सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[] Transliteration in Urdu Script.

[]सभा में यह प्रश्न श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा पूछा गया।

सरकार के पास इस आशय की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि ये या ऐसी कोई फैक्ट्री, पुलिस की मिलिभगत से चल रही हैं।

Rampant manufacturing of illegal arms in the country

*265. SHRI BHAGAT SINGH KOSHYARI:

SHRI PRABHAT JHA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government has got information that illegal arms manufacturing factories are operating openly in several parts of the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government has got information that these factories are running with the connivance of police;

(d) if so, the reasons for not taking serious steps so far; and

(e) the immediate steps Government is going to take against these factories and concerned police officers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN) : (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) Some available inputs suggest that illegal arms and ammunition manufacturing units exist in some States, where manufacturing through clandestine cottage level household units takes place.

Further details in this regard are not readily available and have to be collected from all the States/UTs. Action is in process for collecting the required information and the same will be laid on the Table of the House in due course.

There is no information available with Government to the effect that these or any such factories are running with the connivance of the police.

श्री भगत सिंह कोश्यारी (उत्तराखंड) : माननीय सभापति जी, यह इतना गंभीर विषय है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इतनी सरलता से इस प्रश्न को टाला है। आज यह जो देश में इल्लीगल आर्म्स की बिक्री चल रही है, इसके कारण कितनी ही घटनाएं हो रही हैं। एक प्रकार से जैसे देश में पैरलल इकोनॉमी चलती है, वैसे ही देश के अंदर पैरलल आर्म्स इकोनॉमी चल रही है। जब माननीय मंत्री जी से हमने यह प्रश्न पूछा, तो वह कहते हैं कि "कुछ उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है" "Some available inputs suggest...", which means that he does not have confirmed information about it. महोदय, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि यह इतना गंभीर विषय है और इस विषय में आपने यह कहा है कि केवल 'कुछ उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है।' ऐसे विषय में मैं आपको अखबारों की कितनी ही कटिंग्स दिखा सकता हूं, तो आप मुझसे कहेंगे कि कुछ समय बाद क्वेश्चन को पूछो, लेकिन माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रश्न को बहुत ही हलके ढंग से टाला गया है।

---

* Original notice of the question was received in Hindi

** The question was actually asked on the floor of the House by Shri Bharat Singh Koshyari.

मेरे पास नैशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो की 2003 से 2007 की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट कहती है कि केवल राजधानी दिल्ली के अंदर 2003 से लेकर 2007 तक जितने क्राइम्स हुए, उनमें से 75%, यानी जितने भी व्यक्ति प्रतिवर्ष मारे गए, उनमें से 75% लोगों की इन इल्लीगल आर्म्स के द्वारा हत्याएं की गई हैं, लेकिन मंत्री जी ने प्रश्न को यह कह कर टाल दिया है कि 'कुछ उपलब्ध सूचना से पता चलता है'। फिर उन्होंने दूसरे पैरा में यह भी कह दिया है कि 'इस संबंध में और ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है।' आफ्टरऑल यह आईटी का जमाना है और हम लोगों की बात भी करनी हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग... ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए।

SHRI BHAGAT SINGH KOSHYARI: Sir, a very vague answer has been given here. इसलिए मेरा कहना यह है ....(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री भगत सिंह कोश्यारी : मेरा कहना यह है कि जिन-जिन राज्यों के बारे में यह जो 'कुछ उपलब्ध सूचनाएं' हैं, क्या माननीय मंत्री जी उन्हें यहां बताने की कृपा करेंगे? दूसरा, ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : एक सवाल या दो?

श्री भगत सिंह कोश्यारी : नहीं, सर, यह सवाल एक ही साथ जुड़ा हुआ है, उसी का पार्ट है। That is co-related, Sir. दूसरा, वह यह सूचना कब तक उपलब्ध करवा देंगे? इसे वह निश्चित रूप से बता दें, टाइम बाउंड बता दें, फिर से कुछ वेग न बताएं।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Mr, Chairman, Sir, I take this question very seriously. Data has to be collected from the States. As soon as this question was received, we asked all States and UTs to send us the data. We have reminded them on telephone. We have responses only from Delhi, which is directly under our control, and the Government of Dadra and Nagar Haveli. Other States have not responded. Either they are unable to give data or they are unwilling to give data. But you have my word that I will insist on the States providing me the information and when the information comes from the States, I will place it on the Table of the House. I have taken this quite seriously. But, obviously, it is the States which have to give the data for the action they have taken to unearth illegal arms and ammunition.

श्री भगत सिंह कोश्यारी : माननीय सभापति जी, हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि "I take it very seriously", मैं इसे गंभीरता से ले रहा हूं। मेरे ख्याल से नक्सलवाद को भी आपने बहुत गंभीरता से लिया है और यह अच्छी बात है कि आप हर बात को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री भगत सिंह कोश्यारी : जी हां, मान्यवर, उसी के आधार पर पूछूंगा, आखिर यह गंभीरता का सवाल है तो हमें भी तो गंभीर होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह सिर्फ राज्यों का ही मैटर नहीं है, आफ्टरऑल हम भी सैंटर में, यूनियन में हैं और अगर हम उनसे यहां कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका कोई महत्व भी है, या फिर ऐसा है कि सैंटर का कोई महत्व ही नहीं है और हम सीधे राज्यों पर टाल देंगे।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय ...(**व्यवधान**)... नहीं-नहीं, अगर यह स्टेट मैटर है, then, it means that you should not put this question here. मेरा आपसे अनुरोध यह है कि इस देश के अंदर जहां-जहां यह सारी

फैक्टरीज़ चल रही हैं, एक निश्चित समय सीमा के अंदर, above cast, creed and political consideration, क्या आप इन चीजों पर कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठाएंगे? आपने कहा भी है कि आपके पास सूचनाएं उपलब्ध हैं। यदि आप चाहें तो इसे स्टेट्स के माध्यम से करवाएं। आप ऐसा कदम कब तक उठाएंगे?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, what he is saying is quite right. But, the point is crime investigation is a State-subject. I will be very happy if the entire House agrees that the Central Government through the Central police can, directly take action in respect of arms factories or arms manufacturing; I will be quite happy. If the Leader of the Opposition and an eminent lawyer confirms what Mr. Koshyari says, I will be very happy. The point is, this is a State-subject, crime has to be addressed by the State Governments, crimes have to be investigated by the State Governments. Manufacture of arms without a licence is a crime. So, if all of you say that the Central Government can directly take action, I will be quite happy to do so.

श्री सभापति : श्री प्रभात झा। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : कोई नई कंडीशन आ गई क्या ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : नहीं, नहीं। प्लीज़ आप इन्हें सवाल पूछने दीजिए।

श्री प्रभात झा : गृह मंत्री जी, जो अवैध हथियार पकड़े जाते हैं, पकड़े जाने के बाद उनको स्टोर में रखा जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ये स्टोर में चले जाते हैं, उसके बाद इन पर केस लम्बा चलता है और फिर वे ही हथियार नक्सलियों के पास या माओवादियों के पास कैसे पहुंच जाते हैं? क्या इसको रोकने की कोई व्यवस्था की गई है या इन्हें नष्ट कर दिया जाता है? उन हथियारों का क्या होता है? यही मैं जानना चाहता हूं।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, it is our assessment that there are factories, there are places where arms and ammunition are being manufactured illegally. Our agencies give us some reports from time to time; we share the information with the States and ask the States to take action. It is not that no State has taken action. I have information about some States having taken action. But, there is no formal official reply from the States about the cases they have investigated. When that information comes, I shall certainly place it before the House.

When arms and ammunition are manufactured illegally, obviously, some part of it is sold to naxalites and other militants. But naxalites and other militants also loot places where arms are stored. In fact, they have looted even armouries of State police. The example is what happened in Orissa recently. Therefore, militants have access to illegally manufactured arms; they also loot armouries; they attack police stations and loot arms; therefore, they have access to weapons. It is a grave problem. I have said on another occasion that we will address the problem with all seriousness. I ask for the cooperation of all the State Governments to take strict action against those manufacturing arms and ammunition without a licence.

डा. ऐजाज़ अली : सर, मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा चूंकि मिनिस्टर साहब उर्दू-हिन्दी जरा कम समझते हैं। शहीद हेमन्त करकरे ने मालेगांव बम धमाके के इन्वेस्टिगेशन के मामले में डोमेस्टिक टेरॅरिस्ट्स और मिलिट्री के बीच

नेक्सस की बात भी उठाई थी। यह मामला भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन से कनेक्टेड है। आज पाकिस्तान सिर्फ इसलिए बरबाद है कि ...(**व्यवधान**)...

ڈاکٹر اعجاز علی : سر، میں تھوڑا دھیرے بولوں گا چونکہ منسٹر صاحب اردو-ہندی ذرا کم سمجھتے ہیں۔ شہید مہنت کرکرے نے مالیگاؤں بم دھماکے کے انویسٹیگیشن کے معاملے میں ڈومیسٹک ٹیریرسٹ اور ملٹری کے بیچ نیکسس کی بات بھی اٹھائی تھی۔ یہ معاملہ بھی آرمس اینڈ ایمیونشن سے کنیکٹڈ ہے۔ آج پاکستان صرف اس لئے برباد ہے کہ ...(مداخلت)...

श्री सभापति : आप इस सवाल से सम्बन्धित सवाल पूछिए।

डा. ऐजाज़ अली : सर, यह सवाल ही है। आप पाकिस्तान सिर्फ इसलिए बरबाद है कि वहां मिलिट्री और टेरॅरिस्ट्स के बीच नेक्सस है। हमारे देश को इससे सबक लेना चाहिए। जब देश रहेगा तभी तो हम आपस की लड़ाई लडेंगे! ...(**व्यवधान**)...

ڈاکٹر اعجاز علی : سر، یہ سوال ہی ہے۔ آج پاکستان صرف اس لئے برباد ہے کہ وہاں ملٹری اور ٹیریرسٹ کے بیچ نیکسس ہے۔ ہمارے دیش کو اس سے سبق لینا چاہئے۔ جب دیش رہے گا تبھی تو ہم آپس کی لڑائی لڑیں گے ...(مداخلت)...

श्री सभापति : भई आप सवाल पूछिए न!

डा. ऐजाज़ अली : सर, मुझे यह कहना है कि अगर इस नेक्सस को नहीं तोड़ा गया, तो फिर हमारी भी हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

ڈاکٹر اعجاز علی : سر، مجھے یہ کہنا ہے کہ اگر اس نیکسس کو نہیں توڑا گیا، تو پھر ہماری بھی حالت پاکستان جیسی ہو جائے گی ...(مداخلت)...

श्री सभापति : आपका सवाल क्या है?

डा. ऐजाज़ अली : इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि शहीद हेमन्त करकरे ने इस नेक्सस पर जो उंगली उठाई थी, उसने इसको खत्म करने का इरादा भी जाहिर किया था, तो सरकार ने इस नेक्सस को तोड़ने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं?

ڈاکٹر اعجاز علی : اس لئے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہید ہیمنت کرکرے نے اس نیکسس پر جو انگلی اٹھائی تھی، اس نے اس کو ختم کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا تھا، جو سرکار نے اس نیکسس کو توڑنے کے لئے اب تک کیا قدم اٹھائے ہیں؟

 Transliteration in Urdu Script.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, Karkare was a great police officer, who laid down his life in the aftermath of 26/11 attacks. He was investigating certain cases. There is at least one case which is investigated where army officers are accused. The case is sub judice. I cannot pronounce the guilt or otherwise of the Army Officers. But there is indeed one case where Army officers are accused.

DR. T. SUBBARAM1 REDDY: Sir, it is an important issue. The hon. Minister has replied that, yes, he has some information that illegal arms and ammunition are being manufactured in some States. That means he has the authority to make those States to investigate. Even though it is a State Subject, it is a very serious matter. If it has come to the notice of the Home Ministry, they must take immediate action. I would like to know what action has been taken, if not, why don't you take immediate action to stop people from manufacturing illegal arms in those States, which you have identified?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, what I said was our agencies provide us information from time to time and we have information about States having taken action in respect of some cases of illegal manufacturing of arms. But I cannot place that information before this House until the State officially confirms that that was the case registered, investigated and action taken. I hope that the Members in the House who have been in the Government would know ths distinction between information gathered from agencies and information gathered officially from the State Governments.

SHRI KUMAR DEEPAK DAS: Thank you, Sir. It is a serious matter because the North East has been flooded with illegal arms and we are the worst sufferers. There is a regular supply of illegal arms through the international borders. There are various examples and we have been informed that they have opened some illegal arms manufacturing units in the border areas. I would like to know whether the Government would look into such a serious matter.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I have no information about illegal arms manufacturing units in the North East. But if the States report any such cases, I shall certainly share it with the House. But I have information that a large number of militant groups receive arms from across the border. They smuggle arms into the country through arms purchases from other countries, they are smuggled across the international border into the North East.

Difference in special allowances for CRPF personnel

*266.SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a wide difference in special allowances for CRPF personnel deployed in naxalite areas and militancy affected areas like Jammu and Kashmir and North East; and

(b) if so, why the naxalite affected areas have been kept in a different category even as nearly 300 CRPF personnel have lost their lives in anti-naxal operations so far?